Indian J. Soc. & Pol. 12 (02):91-94: 2025 **ISSN: 2348-0084 (PRINT)**
31 JULY 2025 **ISSN: 2455-2127(ONLINE)**

भारतीय विदेश नीति 'प्रथम पड़ोसी नीति' से विस्तृत पड़ोस नीति तक

अभिषेक कुमार सिंह[1]

[1]शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग,बी0आर0डी0 पी0जी कालेज, बरहज, देवरिया, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर,उ0प्र0,भारत

ABSTRACT

प्रस्तुत शोध पत्र ''भारतीय विदेश नीति 'प्रथम पड़ोस नीति' से विस्तृत विदेश नीति तक'' का विशद् विश्लेषण प्रस्तुत करना है, वस्तुतः अपने पड़ोसी देशो, की तुलना मे, भारत क्षेत्रफल, जनस,ख्या, आर्थिक एव, सैन्य क्षमताओ, के सन्दर्भ मे, अत्यधिक व्यापक स्वरूप धारण करने वाला देश है, भारतीय उपमहाद्वीप मे, स्थित प्रत्येक पड़ोसी देश अन्य पड़ोसी देशो, की तुलना मे, भारत के साथ अधिक नैतिक, भाषाई तथा सा,स्कृतिक विशिष्टाताओ, का आदान–प्रदान करता है, भारत की पड़ोसी देशो, के प्रति और पड़ोसी देशो, की भारत के प्रति 'पड़ोस' की अवधारणा को यह असंतुलन ही आकार प्रदान करता है।

KEYWORDS: *स,ास्कृतिक विशिष्टता, केन्द्रस्थ भाव, समय सापेक्ष, उपमहाद्वीप, हिन्द महासागरीय, नेतृत्वकर्ता,*

हालाँकि स्वाधीनता के उपरांत से ही भारतीय विदेश नीति केन्द्रस्थ भाव मे, अपने पड़ोसी देशो, को स्थान प्रदान करती है जिससे 'प्रथम पड़ोसी नीति' की संकल्पना का सृजन हुआ, इसके परिणाम स्वरूप भारत के विकास सम्बन्धी विविध लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु उसके पड़ोसी देशों का शांतिपूर्वक रहना परमावश्यक है, क्योंकि समय सापेक्ष निरन्तर परिवर्तित होती जटिलताओ, के रूप मे, भारत के पड़ोसी देश भारत के समक्ष नूतन चुनौतियाँ उपस्थित करते है, भौगोलिक रूप से जुड़े होने के कारण पड़ोसी देशो, के साथ भारत का क्षेत्रीय सहयोग अत्यन्त महत्व का हो जाता है, इस वजह से भारत के पड़ोसी देशों द्वारा किसी भी चुनौती का सामना करना भारत मे, भी अपना प्रभाव परिलक्षित कर सकता है, अतएव भारत की 'प्रथम पड़ोसी नीति' अपने पड़ोसी देशों को महत्व प्रदान करने की भारतीय दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित करती है, इससे यह ज्ञात होता है कि इस नीति के माध्यम से भारत न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में वरन् विस्तारित हिन्द महासागरीय क्षेत्र मे, भी स्थायी शांति, स्थिरता तथा समृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रबल आकांक्षी है।

विगत एक दशक में भारत न केवल एक क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में उभरा है वरन् एक वैश्विक नेतृत्वकर्ता की भूमिका में भी अपना सशक्त दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है, भारत अपने पड़ोसी देशो, के साथ सम्बन्धो, की तर्ज पर ही अपनी इस भूमिका को और अधिक सशक्त बनाने हेतु अपने विस्तारित पड़ोसी देशों के साथ भी मजबूत सम्बन्ध स्थापित कर रहा है क्योंकि कुछ देश तेा भौगोलिक रूप से भारत से दूर स्थित है किन्तु उनके भारत के साथ महत्वपूर्ण राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एव, रणनीतिक सम्बन्ध स्थापित है जिस कारण उन्हे, 'विस्तृत पड़ोसी' देशो, के रूप मे, इ,गित किया जाता है, इनमे, हिन्द महासागरीय क्षेत्र के देश, दक्षिण–पूर्वी एशिया के देश या पश्चिम एशिया के देश शामिल है, इस सन्दर्भ में निर्धारित भारतीय विदेश नीति ही 'विस्तृत पड़ोस नीति' की संकल्पना को व्यापक आयाम प्रदान करता है।

यद्यपि 21वीं शताब्दी के वैश्विक परिदृश्य में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को सुनिश्चित करने में 'पड़ोस' महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कथन था कि, ''हम मित्र तो बदल सकते हैं किन्तु अपने पड़ोसी नहीं,''(सिंह , 2017, पृ0 812) हालाँकि यह सच्चाई है कि कोई भी देश जो सुरक्षित, प्रगतिशील एवं विकसित होने का आकांक्षी है उसे यह स्वीकार करना ही होगा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने पूर्व प्रधानमंत्री के इस कथन की गाँठ बाँध ली और सरकार का दायित्व सम्भालने से पूर्व शपथ ग्रहण समारोह में ही 'प्रथम पड़ोस नीति' का अनुकरण करते हुए पड़ोसी देशों के शासनाध्यक्षों को निमंत्रण देकर एक मिसाल पेश किया तथा 'विस्तृत पड़ोसी नीति' के तहत पड़ोसी देशों के साथ–साथ समूची दुनिया को यह संदेश देते हुए पड़ोसियों से मैत्री भाव का संदेश देकर विस्तृत पड़ोस के मध्य विश्वसनीयता की अभिवृद्धि हेतु मार्ग प्रशस्त किया, सी0 राजामोहन का इस सम्बन्ध में कथन है कि, ''अपने पड़ोसियों के मध्य प्रधानता बनसए बिना कोई भी राष्ट्र वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय शक्ति नहीं बन सकता है,''(राजामोहन,2007) उन्होंने विश्व समुदाय को यह बताना सुनिश्चित किया कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने पड़ोस मे, शांति और स्थिरता का पक्षधर है, वर्तमान युग में किसी भी देश की शांतिप्रियता का एक वास्तविक मानक यही है कि उसके अपने पड़ोसियों से सम्बन्ध मधुरतम् है, अथवा नहीं? पड़ोसियों से सम्बन्धों के सुधार की कोशिश के साथ यह नितांत अपरिहार्य है कि नूतन सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा हेतु कटिबद्ध रहे, हालाँकि भारत के पड़ोसी देशों के प्रकृति को समझना अत्यन्त जटिल है, इसके पड़ोसियो, की राजनीतिक एवं आर्थिक दशाएं भिन्न–भिन्न हैं भारतीय

1: Corresponding Author

विदेश नीति इनके मध्य परस्पर घनिष्ठ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक सम्बन्धों के साथ–साथ उनके द्वारा प्रत्युत्पन्न राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष खतरे को परिभाषित करती है, इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बाँग्लादेश, चीन, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे देश है, भारत के साथ सभ्यता आधारित सम्बन्ध स्थापित करने वाले ये देश साँझी संस्कृति, साँझा इतिहास एवं लोगों के मध्य परस्पर सम्बन्ध जैसी विशिष्टताओं से आबद्ध है, स्वतंत्रता के बाद से ही ये निकटतम् पड़ोसी भारतीय विदेश नीति की ''प्राथमिकता की प्रथम परिधि'' में सम्मिलित रहे हैं अपेक्षाकृत यदि ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सजग रहे,, प्रधानमंत्री मोदी जी का संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की 69वीं सभा को सम्बोधित करते हुए कथन था कि ''एक राष्ट्र का भाग्य उसके पड़ोस से सम्बन्धित होता है, अतएव मेरी सरकार अपने पड़ोसियों के साथ मित्रता एवं सहयोग को अग्रेतर करने को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है,''(दास, 2009) प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षेस को क्षेत्रीय शांति एवं विकास तथा पड़ोसी राष्ट्रों के मध्य परस्पर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हेतु अत्यन्त महत्वपूर्ण माना, दक्षेस राष्ट्रों के साथ सम्बन्धों पर बल देते हुए उनका कथन था कि ''समस्त दक्षिण एशियाई राष्ट्र हमारी विकास यात्रा के सहयोगी हैं, दक्षिण एशिया के प्रति मेरा दृष्टिकोण वैसा ही है जैसा भारत के प्रति है – सबका साथ, सबका विकास,''(चौलिया, 2016,पृ098)

वस्तुतः प्रधानमंत्री मोदी जी का यह उद्घोष न केवल भारतीय राष्ट्रीय गवर्नेंस तक सीमित है अपितु यह 'पड़ोसवादी नीति का संचालक' भी हैं दक्षेस के 18वें शिखर सम्मेलन नवम्बर 2014, को काठमाण्डू (नेपाल) में क्षेत्रीय सम्बन्धों को सुदृढ़ करने, स्वास्थ्य एव, शिक्षा के क्षेत्र मे, सहयोग तथा बुनियादी ढाँचे के विकास पर बल दिया, आर्थिक कूटनीति को प्रोत्साहित करते हुए उनका कथन था कि, ''इस क्षेत्र के प्रति हमारी दृष्टि पाँच स्तम्भों : व्यापार, निवेश, सहायता, प्रत्येक क्षेत्र में सहयोग तथा सभी लोगों के मध्य सहजतम् सम्पर्क पर टिकी है,''(चौधरी,2016,पृ03) यद्यपि यह नीति भारत के परामर्शदात्री, गैर बराबरी और विकासोन्मुख दृष्टिकोण से अभिप्रेरित है, गौरतलब है कि गैर बराबरी सम्बन्धों का अभिप्राय पड़ोसी देशों के साथ निःस्वार्थपूर्वक सहयोगात्मक नीति को आत्मसात् करना है,

हालाँकि 'विस्तृत पड़ोसी देश' भारत के वैश्विक नेतृत्व के प्रवेश द्वार के रूप में परिलक्षित होते हैं क्योंकि भारत आज एक क्षेत्रीय महाशक्ति बनने और वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निर्वहन करने का प्रबल आकांक्षी है, इसी कारण वह अपने निकटतम् पड़ोसी देशों के साथ सम्बन्धों के समान ही अपने विस्तारित पड़ोसी देशों के साथ भी मजबूत एवं घनिष्ठ सम्बन्ध बना रहा है, भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति' एशिया–प्रशांत क्षेत्र के लिए एक प्रमुख राजनयिक पहल है जिसका उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्तरों पर इस क्षेत्र के साथ आर्थिकं रणनीतिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धों की अभिवृद्धि करना है, यह नीति चार केन्द्रीय विषयों (4-C) पर अवलम्बित हैं यथा – Connectivity - जुड़ाव, Commerce – वाणिज्य, Culture – स,स्कृति और Capacity Building – क्षमता निर्माण,

वस्तुतः पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भाँति, प्रधानमंत्री मोदी भी 'थिंक वेस्ट नीति' को नई ऊर्जा देकर भारतीय विदेश नीति में इसे प्राथमिकता प्रदान किया है, अर्थात् भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए पश्चिमी देशों की अनदेखी नहीं कर सकता है, अतएव प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 'पूर्व की ओर सक्रियता की नीति' के साथ–साथ 'पश्चिम की ओर देखो, की नीति' पर भी विशिष्ट रूप से ध्यान दिया जा रहा है, तत्कालीन विदेश सचिव एस0 जयशंकर ने नई दिल्ली में अपने उद्घोषणा में 'थिंक वेस्ट नीति' शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि, ''इन देशों के मध्य अन्तःक्रिया हमें सहयोग का एक नूतन मार्ग प्रशस्त करेगीं मैं आत्मविश्वासपूर्वक यह अनुमान लगा सकता हूँ कि 'एक्ट ईस्ट का मिलान थिंक वेस्ट' के साथ होगा।

यद्यपि भारत की यह नीति हिन्द–प्रशान्त क्षेत्र हेतु समावेशिता, खुलेपन और आसियान केन्द्रीयता की अवधारणा पर अवलम्बित है, भारतीय विदेशनीति समुद्र को विशेष महत्व प्रदान कर रही है, हिन्द–प्रशांत क्षेत्र भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भविष्य में एशिया में शक्ति संतुलन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा, क्योंकि वर्तमान समय में हिन्द महासागर वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण स्रोत एवं प्रतिस्पर्धी क्षेत्र बनकर वैश्विक क्षितिज पर दस्तक दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी का इस सन्दर्भ में मत है कि भारत शांतिपूर्ण एवं समृद्ध हिन्द–प्रशांत क्षेत्र हेतु प्रतिबद्ध हैं भारत इसकी सुरक्षा हेतु तत्पर है और इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा हैं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार का कथन है कि, ''प्रधानमंत्री मोदी शांतिपूर्ण अनावृत्त एवं समावेशी हिन्द–प्रशांत क्षेत्र की दृष्टि से समुद्री सहयोग को सुदृढ़ करने तथा एक संतुलित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी संधि के विजन हेतु प्रतिबद्ध हैं''(इण्डियन एक्सप्रेस, 16 मार्च 2016)हालाँकि सागरीय क्षेत्र के अन्तर्गत व्याप्त शब्द सागर (SaGaR) को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने शब्दों में व्याख्यायित करते हुए कहा कि, सागर से तात्पर्य Security and Growth for all in the region (SaGaR) से है, अर्थात् इस क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा एवं विकास की उपलब्धता कराना है, हिन्द महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव का प्रत्युत्तर देने के उद्देश्य से ही प्रधानमंत्री इस क्षेत्र को अत्यधिक महत्व प्रदान कर रहे हैं, अतएव हिन्द महासागर भारतीय विदेशी नीति में सर्वोच्च स्थान रखता है जिसके तहत हिन्द महासागर में सागरवर्ती प्रभुत्व को कायम रखना हैं।(सिह, 2017 पृ0 202)

वस्तुतः विस्तारित पड़ोस की नीति समुद्रतटीय अफ्रीकी देशों हेतु Developing Together is equal की भावना को चरितार्थ करती है, मध्य एशिया के क्षेत्र में भारत ने आर्थिक और सांस्कृतिक सम्बन्धों को अधिक घनिष्ठ रूप प्रदान करने के लिए Connect Central asia Policy को आत्मसात् किया है, खाड़ी सहयोग परिषद् (Gulf co-operation Council) तथा भारत–मध्य पूर्व–यूरोप आर्थिक

गलियारा (India-Middle East-Europe Economic Corridor) का प्रस्तावित होना इस क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति को प्रमाणित करता हैं।

यद्यपि अतीतकालीन भारतीय राजनीति में पड़ोसी राज्यों के प्रति निर्मित की गई नीतियाँ परिलक्षित होती है जो पड़ोसी राज्य के साथ सम्बन्ध निर्धारण में मार्गदर्शक का कार्य करती थीं तीसरी शताब्दी ई0पू0 भारतीय राजशास्त्र के आचार्य चाणक्य ने राजव्यवस्था में पड़ोसी राज्यों के साथ सम्बन्धों के निर्धारण हेतु 'मण्डल सिद्धान्त' का प्रतिपादन किया था जिससे यह ज्ञात होता है कि आपका पड़ोसी आपका स्वाभाविक शत्रु होता है और पड़ोसी का पड़ोसी आपका मित्र होता है, 'मण्डल सिद्धान्त' से यह ज्ञात होता है कि राष्ट्र (भारत) को अपनी सम्प्रभुता की रक्षा हेतु निकटतम् एवं विस्तृत पड़ोसियों से कितना शक्ति संतुलन बनाए रखना हैं आचार्य कौटिल्य ने 'मण्डल सिद्धान्त' के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए छः सूत्रीय विदेश नीति की अनुशंसा किया है यथा – सह–अस्तित्वं तटस्थता, गठबन्धन, दोहरीनीति, कूच और युद्ध, राजा को इस विदेशनीति को प्रयोग में लोने हेतु उन्होंने पांच युक्तियाँ अपनाने का परामर्श प्रदान किया है, यथा – संधि, उपहार, रिश्वत, असहमति, छल, दिखावा तथा खुला हमला अथवा युद्ध, संधियो, एवं गठबन्धन के प्रश्न पर उनका स्पष्ट सुझाव है कि, ''एक राजा को ऐसी किसी भी मित्रता या गठबन्धन को तोड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए जो अग्रेतर उसके हित हेतु नुकसानदेह सिद्ध हों''।(अहमद, 2017,पृ076)

वर्तमान भू–राजनीतिक परिदृश्य में भारत की पड़ोस नीति की प्रासंगिकता

वस्तुतः भौगोलिक की दृष्टि से पड़ोसी देश किसी भी देश की वास्तविक कूटनीति का प्रथम सोपान एवं विकास की धुरी होते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि, भू–राजनीतिक सशक्तता एवं सामाजिक विकास हेतु पड़ोसी देशों के साथ भारत के सम्बन्ध महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं भू–सामरिक हित की दृष्टि से क्षेत्रीय नेतृत्व में हिन्द महासागरीय क्षेत्र वैश्विक सामरिक स्पर्धा का उभरता हुआ महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है जिसमें पड़ोसियों के साथ सामंजस्यपूर्ण सहयोग से ही दक्षिण एशिया में भारत की केन्द्रीय भूमिका को सशक्तता प्राप्त हो सकती है, पड़ोसियों के सहयेाग से ही भारत चीन के प्रभाव को कमतर करते हुए प्रतिसंतुलित करने तथा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनने के महत्वपूर्ण आकांक्षा को पूर्ण कर सकता है।

यद्यपि भारतीय विदेश नीति को विविध बहुपक्षीय संगठनों यथा– संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), विश्व व्यापार संगठन (WTO), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के मंचों पर दक्षिणी राष्ट्रों के नेतृत्वकर्ता के रूप में सशक्त उपस्थिति दर्ज करने हेतु भी पड़ोसी राष्ट्रों के सहयोग की अपेक्षा है, भारत को विविध बहुपक्षीय मंचो, पर अपने पड़ोसियों को सहयोग करने से ही द्विपक्षीय सम्बन्धों में एक क्षेत्रीय या उपक्षेत्रीय आयाम प्राप्त हुआ है, इससे इस क्षेत्र की श्रेष्ठतम् समक्ष विकसित करने में सहायता प्राप्त होगी।

वस्तुतः आर्थिक हित की दृष्टि से ऊर्जा सुरक्षा हेतु भारत अपने उत्तरी क्षेत्र के पड़ोसी देशों में जल–विद्युत की अपार सम्भावनाओं को सुनिश्चित किया है, इसके साथ ही प्राकृतिक गैस एवं तेल के आयात में किसी भी संकट से निपटने हेतु भारत को हिन्द महासागरीय क्षेत्र के पड़ोसी देश के सहयोग की अत्यन्त आवश्यकता होगी क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता का अधिकतम् कच्चा तेल एवं आधे से अधिक प्राकृतिक गैस दुनिया के विभिन्न भागों से आयात इन्हीं समुद्री मार्गों द्वारा करता है, अतएव हिन्द महासागरीय पड़ोसियों से भारत का मधुरतम् सम्बन्ध इसके आर्थिक हित साधना में सहायक होगा।

यद्यपि सुरक्षा की दृष्टि से भारत को ऐसे पड़ोसियों की आवश्यकता है जो उसकी सम्प्रभुता एवं क्षेत्रीय अखण्डता का सम्मान करे तथा किसी भी अलगाववादी या आतंकवादी संगठनों को भारत के विरूद्ध अपनी भूमि का उपयोग की अनुमति प्रदान न करे, उदाहरण स्वरूप भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को नष्ट करने में म्यांमार एक प्रमुख सहयोगी राष्ट्र के रूप मे, दृष्टव्य है, सामुद्रिक मार्ग के माध्यम से होने वाले आतंकी हमलों की चुनौतियों से सुरखा हेतु भारत को ऐसे पड़ोसी देशों के सहयोग की अपेक्षा से जिससे उसे अपने प्रादेशिक जल क्षेत्र की निगरानी करने में सहायता प्राप्त हो सके, कूटनीतिक अथवा सामरिक दृष्टि से भारत अपने पड़ोसियों के साथ सशक्त सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध स्थापित करके विविध सांस्कृतिक मूल्यों तथा अपने साफ्टपॉवर (Soft Power) के प्रभाव को और अधिक बढ़ा सकता हैं।

भारत के 'प्रथम पड़ोस नीति' एवं 'विस्तृत पड़ोस नीति' को सशक्त एवं प्रभावशाली बनाने के उपाय –

भारत द्वारा इस नीति को स्थायित्व एवं प्रभावशाली बनाने हेतु निम्न रणनीतिक उपाय पर विमर्श की आवश्यकता है –

- क्षेत्रीय संगठनों को पुनर्जीवित करना,
- पाक प्रायोजित आतंकवाद को समाप्त करना,
- चीन के साथ संवाद स्थापित करना,
- आंतरिक सुरक्षा संरचना को सुदृढ़ करना,
- वैश्विक शक्तियों के साथ सहयोग स्थापित करना,
- छोटे पड़ोसी देशों के साथ बेहतर सहभागिता करना,
- श्रेष्ठतम जुड़ाव के समक्ष उपस्थित कमियों को दूर करना,
- जल विवाद का समाधान एवं पर्यावरण संरक्षण में सहयोग प्रदान करना,
- पर्यटन को प्रोत्साहित करना,

अतएव भारत की 'पड़ोस प्रथम नीति' से 'विस्तृत पड़ोस नीति' वाली विदेश नीति गत्यात्मकता का पोषक है, भारतीय विदेश

नीति क्षेत्रीय परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर इस क्षेत्र में भारतीय प्रासंगिक हितों की उचित समायोजना निर्दिष्ट करती रहती हें अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दक्षिण एशिया एवं अन्य क्षेत्रों के भविष्य को मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती रहेगीं भारत अपने 'प्रथम पड़ोस' अथवा निकटतम् पड़ोस तथा विस्तृत पड़ोस के देशेा, का विषम परिस्थितियों में सहयोग प्रदान करने तथा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अग्रज की भांति काम करने हेतु सदैव प्रतिबद्ध रहा हैं तत्कालीन परिस्थिति में स्थिर एवं समृद्ध पड़ोस को सुनिश्चित करेन हेतु बृहतम् दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो भारतीय विदेश नीति के उद्देश्यों एवं राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हो, भारत इस दिशा में सतत् प्रयत्नशील हैं'।

REFERENCES

यामिनी चौधरी और अनुशुआ दिया चौधरी, (2016) *मोदी एंड द वर्ल्डः द रिंग व्यू इनसाइड आउट,* नई दिल्ली, ब्लूम्सबरी,

कबीर तनेजा, थिंक वेस्टः मोदी की सऊदी यात्रां प्राप्तः 24 जुलाईं 2019, स्रोतः http://diplomat-com/2016/03/think&west&modis&visit&to&saudi&arabia%

भारत इंडो–पैसिफिक क्षेत्र में शांति और समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध हैः प्रधानमंत्री मोदी, *द इंडियन एक्सप्रेस,* 16 नवम्बर, 2018, पृ. 6,

चौलिया, श्रीराम (2016) *मोदी डॉक्ट्रिनः भारत के प्रधानमंत्री की विदेश नीति,* नई दिल्ली, ब्लूम्सबरी

मोहन, सी. राजा,(2007) भारत की पड़ोसी नीतिः चार आयाम, *इंडियन फॉरेन अफेयर्स जर्नल,* खंड **2,** अंक **1,** 2007,

अहमद सलीम, (2017) मोदी शासन के दौर में भारत–नेपाल संबंधः चीन की चुनौती, *वर्ल्ड फोकस* (भारत की विदेश नीति श्रृंखला–2), दिसम्बर 2017

अहमद,, डॉ. सलीम मोदी शासन के दौर में भारत–श्रीलंका संबंधः चीन की चुनौती, *वर्ल्ड फोकस* (भारत की विदेश नीति), अप्रैल 2018

सिंह, नरेंद्र (2017) *भारत की सुरक्षा नीतिः मोदी डॉक्ट्रिन,* नई दिल्ली, पेंटागन प्रेस

दास, अंगना (2009) भारत की पड़ोसी नीतिः चुनौतियाँ और संभावनाएँ, *जिंदल जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स,* खंड **4,** अंक **1,** 2009,